



उत्तर प्रदेश के लिये औद्योगिक लाभ

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2024 को उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, उद्योगपतियों और व्यापारियों ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है, जिन्होंने वित्त मंत्री के नरिण्यों की साहसिक तथा आशाजनक बताते हुए प्रशंसा की है।

- उन्हें विश्वास है कि इससे उत्तर प्रदेश को काफी लाभ होगा, क्योंकि इससे वह कुशल कार्यबल, बढ़ी हुई सहायता और विभिन्न क्षेत्रों में खर्च के साथ वनिरिमाण केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।

मुख्य बढि:

- सूत्रों के अनुसार, **शहरी आवास परियोजनाओं** के लिये **10 लाख करोड़ रुपए** के आवंटन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में **कफायती आवास की कमी को दूर करना** है।
 - **प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना** से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ मल्लिगा, जबकि निजी भागीदारी के माध्यम से करिये के आवास को बढावा देने से शहरी मलनि बस्तियों को कम करने में मदद मल्लिगी।
- महिलाओं पर लक्षति पहलों को प्राथमकता देना **लैंगिक समानता** और **सशक्तिकरण** को बढावा देने की दशिा में एक सराहनीय कदम है।
- कृषि, नवाचार, सुधार और अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले नौ **प्रमुख फोकस क्षेत्र** सतत् प्रगति के लिये एक स्पष्ट बलूपरटि प्रदान करते हैं।
- **मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढाकर 20 लाख रुपए करने से** उत्तर प्रदेश के कई छोटे व्यवसाय मालकों को पर्याप्त सहायता मल्लिगी।
 - वनिरिमाण क्षेत्र के परतभागियों के लिये ऋण गारंटी योजना उन्हें **नई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में नविश करने** के लिये प्रेरति करेगी।
 - **वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST)** तथा **आयकर** अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थति करना **सटार्ट-अपस और युवा व्यवसाय मालकों के लिये लाभदायक** होगा।
- कृषि क्षेत्र के लिये 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन और **सबजी उत्पादन को बढावा देने के लिये एक नई क्लस्टर योजना की घोषणा** से देश में **प्रमाणीकरण** तथा **ब्रांडिंग** के माध्यम से **दलहन एवं तलहन** के उत्पादन का वसितार होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- इसे **25 जून, 2015** को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक **शहरी क्षेत्रों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराना** है।
- इसका कार्यान्वयन **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय** द्वारा किया गया।
- **वशिषताएँ:**
 - पात्र शहरी गरीबों को पक्का मकान सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहति **शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना**।
 - मशिा में **संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है**, जिसमें सांघिकि कसूबे, अधसूचिति योजना क्षेत्र, विकास प्राधकिरण, वशिष क्षेत्र विकास प्राधकिरण, औद्योगिकि विकास प्राधकिरण या राज्य वधिान के तहत कोई भी ऐसा प्राधकिरण शामिल है, जिसि शहरी नयिोजन एवं वनियिमन का कार्य सौपा गया है।
 - प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अंतर्गत सभी घरों में **शौचालय, जलापूरति, वदियुत और रसोई जैसी बुनयादी सुवधिाएँ उपलब्ध हैं**।
 - मशिा महिला सदस्यों के नाम पर या संयुक्त नाम पर मकान का स्वामतिव प्रदान करके **महिला सशक्तिकरण को बढावा** देता है।
 - इसके अतरिकित **दवियांग व्यक्तियों, वरषित नागरिकों, अनुसूचिति जातियों, अनुसूचिति जनजातियों, अन्य पछिडे वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षति वर्गों को भी प्राथमकता दी जाती है**।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana- PMMY)

- इसे सरकार द्वारा वर्ष 2015 में गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को **10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने** के लिये लॉन्च किया गया था।
- **वतिापोषण प्रावधान:**
 - **मुद्रा (MUDRA)**, जिसका पूरा नाम **माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड** है, सरकार द्वारा स्थापित एक वतितीय

संस्था है।

- यह बैंकों, **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFC)** और **सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Micro Finance Institutions- MFI)** जैसे विभिन्न अंतर्-मील वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करता है।
- मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्यमियों/व्यक्तियों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देती है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/industrial-gain-for-uttar-pradesh>

